

253

318

**प्रधानमंत्री गति-शक्ति परियोजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय की
अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (EGoS) की समीक्षा बैठक
दिनांक 06.10.2022 का कार्यवाही विवरण**

-00-

प्रधानमंत्री गति-शक्ति परियोजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2022 बजे मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर में विडियों कांफ्रेंसिंग एवं भौतिक रूप के माध्यम से प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की समीक्षा हेतु EGoS (Empowered Group Of Secretaries) की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में निम्नानुसार विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ।

- बैठक में सर्वप्रथम सुश्री जीविषा जोशी गंगोपाध्याय, उप सचिव (लॉजिस्टिक) भारत सरकार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा निम्नांकित एजेण्डा अनुसार चर्चा की गई।

बेसिक 28 लेयर की स्थिति -

उप सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि भारत शासन द्वारा निर्धारित 28 बेसिक लेयर्स में से 21 लेयर छ.ग. राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा पूर्णतः/आंशिक अपलोड किये जा चुके हैं। इन लेयर्स में से 04 लेयर (Embankment, CRZ , Economic Zone) छत्तीसगढ़ राज्य हेतु लागू नहीं है। उप सचिव महोदय द्वारा Bus Shelter/Terminal जो कि पूर्व में राज्य हेतु लागू नहीं था, के संबंध में पुनः विचार करने का सुझाव दिया गया।

उपरोक्त संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा Bus Shelter/Terminal संबंधी जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं पंचायत विभाग से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

उप सचिव महोदय द्वारा 03 बेसिक लेयर Sewer Line, Traffic Lights एवं सरकारी कार्यालयों, जो कि पोर्टल में अद्यतन अपलोड नहीं किये गये हैं के संदर्भ में बैठक में अवगत कराया गया ।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा Sewer Line एवं Traffic Lights की जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त कर अपलोड किये जाने के आदेश दिये गये । नोडल अधिकारी, पीएम गतिशक्ति योजना द्वारा सरकारी कार्यालयों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय को बताया गया कि सरकारी कार्यालयों की GIS Location हेतु BISAG-N को मोबाइल एप्लीकेशन के निर्माण हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा उप सचिव, भारत शासन को पोर्टल में अपलोड किये जा चुके आंशिक डाटा के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि पोर्टल में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये जिससे पूर्व में अपलोड डाटा से वर्तमान में किये गये अपलोड पश्चात् हुई वृद्धि को प्रतिशत अथवा ग्राफ में देखा जा सके, जिससे लेयर संबंधी समीक्षा उचित ढंग से हो सके।

समितियों के गठन के संबंध में -

उप सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि राज्य में EGoS, NPG एवं TSU तीनों का गठन किया जा चुका है। TSU के संबंध में उप सचिव महोदय द्वारा कहा गया कि राज्य में TSU सदस्य में मूलतः विभागों के अधिकारी/कर्मचारी हैं परन्तु भारत शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन्स के अनुसार TSU हेतु विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने के निर्देश

254
319

थे। चूंकि राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण समय-समय पर होता रहता है। जिससे योजना के क्रियान्वयन में बाधा आती है अतः राज्य को TSU हेतु विषय विशेषज्ञ Hire किये जाने का सुझाव दिया गया।

इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा उप सचिव भारत शासन को सुझाव दिया गया कि भारत शासन आकांक्षी जिलों जैसे अन्य योजनाओं में विषय विशेषज्ञ नियुक्त करती है उसी प्रकार राज्य के लिये भी भारत शासन विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकती है। उप सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि PMU (Project Management Unit) के लिये विषय विशेषज्ञ Hire किये जाने हेतु राज्य शासन हेतु आबंटित वार्षिक बजट का उपयोग किया जा सकता है।

State Annual Action Plan 2022-23

उप सचिव महोदय द्वारा Annual Action Plan के तहत प्रेषित 12 फूडपार्क (97.94 करोड़) एफसीआई अप्रोच रोड़ (4.64 करोड़), छ.ग. राज्य GIS प्रोजेक्ट (50 करोड़) के तकनीकी अनुमोदन एवं DPR आदि सर्पोटिंग दस्तावेज प्रेषित करने को कहा।

तत्पश्चात् उप सचिव महोदय द्वारा अन्य राज्यों द्वारा निर्मित टूल्स एवं स्टेट मास्टर प्लान के संबंध में बताया गया।

- मुख्य सचिव महोदय द्वारा उप सचिव महोदय को सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में DPIIT द्वारा राज्य हेतु व्यक्ति विशेष को नामित किया जाये जिससे अन्य राज्यों में किये जाने वाले कार्यों एवं NMP से संबंधित कार्यों से राज्य अवगत हो सके।
- मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की समीक्षा प्रतिमाह किये जाने के निर्देश दिये गये। इस बैठक में राजस्व विभाग संबंधी समीक्षा के अतिरिक्त अन्य विभागों के लंबित डाटा अपलोड संबंधी समीक्षा की जावेगी।

बैठक में EGoS (Empowered Group Of Secretaries) के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक आभार प्रदर्शन के साथ समाप्त हुई।

Lawal
7/11/22

(एम.एल.पवार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग